डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 मई, 2022, डिस्पेच दिनांक 16 मई, 2022

| वर्ष 65 | अंक 24 | भोपाल | 16 मई, 2022 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

मुख्यमंत्री श्री चौहान को मत्स्य महासंघ ने भेंट किया 5 करोड़ 11 लाख का चेक

मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट भी रहे उपस्थित

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को मंत्रालय में जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य-विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ की ओर से मत्स्य उत्पादन लाभांश का 5 करोड़ 11 लाख रूपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्री श्री सिलावट और मत्स्य महासंघ को निरंतर उत्कृष्ट कार्य एवं प्रयास के लिए बधाई और शुभकामनाएँ दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐसे ही विकास कार्यों से प्रदेश की प्रगति और उन्नति होगी और हम आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में सफल होंगे। प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण तथा मत्स्य-विकास श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव और मत्स्य महासंघ के अधिकारी उपस्थित थे।

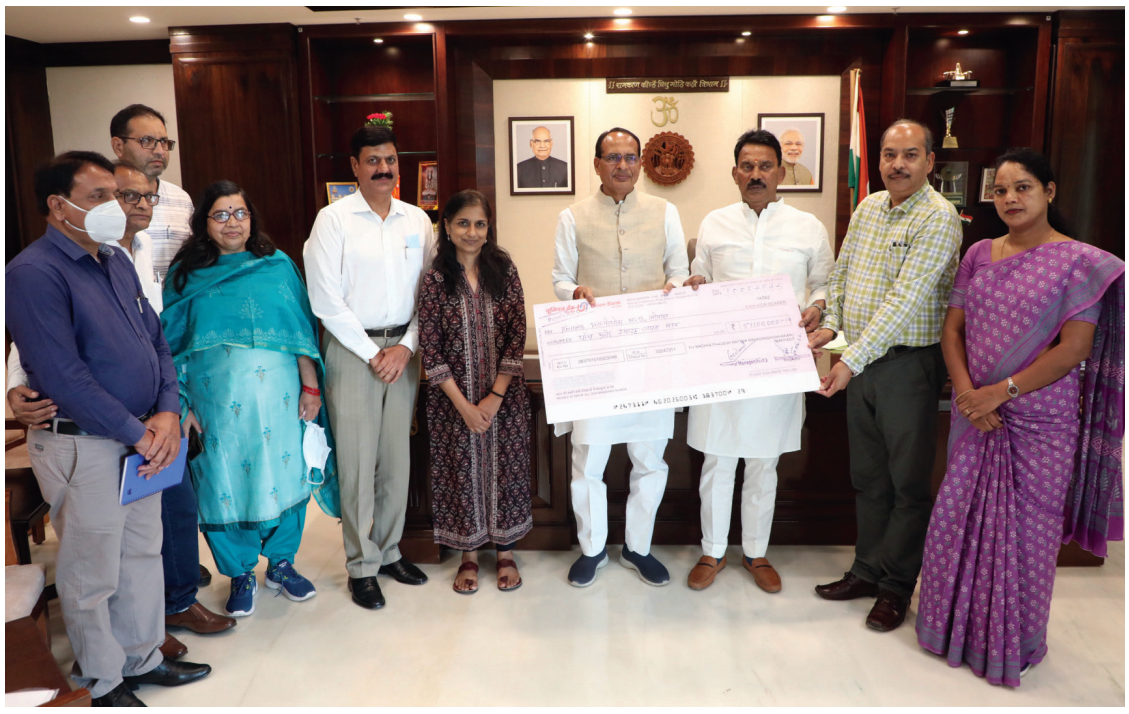

राज्य शासन द्वारा मत्स्योद्योग विकास, रख-रखाव और मछली के व्यापार के लिए मत्स्य महासंघ को 2 लाख 31 हजार हेक्टेयर जल क्षेत्र सौंपा गया है। मत्स्य महासंघ के जलाशयों में मछली पकड़ने का कार्य, जलाशय के आस-पास रहने वाले स्थानीय परंपरागत मछुआरों को दिया जाता है। जलाशयों के निर्माण से विस्थापित और प्रभावित हुए व्यक्तियों को भी मछली पकड़ने के कार्य से जोड़ा जाता है। स्थानीय परंपरागत मछुआरों और जलाशयों के निर्माण से विस्थापित और प्रभावित व्यक्तियों की सहकारी समितियाँ बनाकर इन गतिविधियों का संचालन किया जाता है। साथ ही मछुआरों को उनके निवास स्थल के समीप ही जीविकोपार्जन के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

मत्स्य महासंघ के जलाशयों से उत्पादित मछली के लिए महासंघ 6 रूपए प्रति किलो की दर से राज्य शासन को रॉयल्टी का भुगतान करता है। इस व्यवस्था में मत्स्य महासंघ के जलाशयों से वर्ष 2021-22 में हुए उत्पादन के लिए 5 करोड़ 11 लाख रूपए की रॉयल्टी का भुगतान राज्य शासन को किया गया। मत्स्य महासंघ द्वारा मछुआरों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए अनेक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। सहकारी बैंकों से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना निरन्तर रहेगी जारी

भोपाल : सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वर्ष 2021-22 की अल्पावधि फसल ऋण योजना निरन्तर जारी रहेगी। राज्य शासन द्वारा योजना को तय शर्तो के अधीन निरन्तर जारी रखने का निर्णय लिया है।

प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता ने बताया कि योजना की शर्तो में वर्ष 2021-22 हेतु बेसरेट वर्ष 2020-21 की तरह 10 प्रतिशत रहेगा। खरीफ 2021 सीजन की ड्यू डेट 15 अप्रैल और रबी 2021-22 सीजन की ड्यू डेट 15 जून 2022 रहेगी। योजना केन्द्र सरकार के निर्देशों के अधीन लागू होगी। योजना में निर्धारित बेसरेट 10 प्रतिशत के अधीन खरीफ और रबी सीजन में अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों के लिए 1 प्रतिशत(सामान्य) ब्याज अनुदान और निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत (अतिरिक्त) ब्याज अनुदान प्रोत्साहन स्वरूप राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।

किसानों के हित में रबी उपार्जन नीति में किए नए प्रावधान : खाद्य मंत्री श्री सिंह

नई उपार्जन नीति होगी और अधिक सहज और सरल

भोपाल : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि वर्ष 2022-23 में उपार्जन नीति को और अधिक सहज और सरल बनाने के लिए नीति में नये प्रावधान किए गए हैं। किसानों के लिए पंजीयन में नॉमिनी की व्यवस्था का प्रावधान कर 28 हजार 298 नॉमिनी पंजीकृत किए गए। पंजीयन को और अधिक सरल करते हुए 3479 वर्तमान पंजीयन केन्द्रों के अतिरिक्त 16 हजार 644 अतिरिक्त पंजीयन केन्द्रों पर कियोस्क से पंजीयन की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त नीति में आधार विहीन एवं शारीरिक रूप से अक्षम किसानों के लिए पंजीयन की व्यवस्था की गई है। मंत्री श्री सिंह ने मंत्रालय में उपार्जन संबंधी कार्यों

के बारे में परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह जानकारी दी।

उपार्जन एवं भुगतान

मंत्री श्री सिंह ने बताया कि पंजीयन केन्द्रों पर बायोमेट्रिक डिवाईस की अनिवार्यता के साथ एसएमएस के स्थान पर स्लाट बुकिंग का प्रावधान किया गया है। इसमें किसान द्वारा उपज विक्रय के लिए उपार्जन केन्द्र का स्वयं चयन किया जा सकेगा। इसके अलावा उपार्जन प्रभारी, किसान के आधार, ई-केवायसी में ओटीपी/बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर खरीदी देयक जारी करेगा।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

कलेक्टर श्री लवानिया ने जिला सहकारी बैंक की समीक्षा की

भोपाल : भोपाल को - ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड भोपाल की बैंक प्रशासक के रूप में कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने बैंक के क्रियाकलापों की समीक्षा की। भोपाल जिला सहकारी बैंक प्रधान कार्यालय के सभागार में संपन्न बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी बैंक तथा प्रधान कार्यालय के अधिकारीगणों के साथ - साथ कृषि शाखा के प्रबंधकों ने भाग भी लिया।

बैंक प्रशासक एवं कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया द्वारा बैंक की वित्तीय स्थिति में कृषक सदस्यों को फसल ऋण वितरण, वर्ष 2021-22 में वितरित कृषि ऋणों की वसूली, अकृषि ऋण वितरण की वसूली, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश योजनांतर्गत कार्यवाही, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, स्प्रिंट अभियान, जिले में पैक्स के माध्यम से कृषि आदान के भण्डारण और वितरण वर्ष 2022-23 में जिले में किये गए उपार्जन आदि की समीक्षा की।

जिले की पैक्स समितियों के अंकेक्षण, बैंक के वर्ष 2021-22 अंतर्गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण, बैंक द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सुविधाएं आदि विषयों पर समीक्षा कर निर्देश दिये गये कि कृषि एवं अकृषि ऋणों की 95 प्रतिशत वसूली माह जून 2022 तक किया जाना सुनश्चित करें। उन्होंने आवश्यकता अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए।

42 लाख से अधिक लाड़ली लक्ष्मियों के कारण आज मेरा मुख्यमंत्री बनना हो गया सफल : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री चौहान की लाड़ली लक्ष्मियों से अपील, माता-पिता का हमेशा करें सम्मान

12 वीं पास करने के बाद कॉलेज में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को दिए जाएंगे 25 हजार रूपये

हर साल 2 मई से 12 मई तक मनाया जाएगा लाड़ली लक्ष्मी उत्सव

लाड़ली लक्ष्मियों के लिए अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायत घोषित होगी लाड़ली लक्ष्मी पंचायत

मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम या कोई भी संस्थान में प्रवेश की पूरी फीस सरकार भरेगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 का किया शुभारंभ

लाड़ली लक्ष्मी उत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जुड़ा पूरा प्रदेश

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटियों के चेहरों पर मुस्कान आती है तो मेरी जिंदगी सफल हो जाती है। आज मेरी जिंदगी सफल हो गई और मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। प्रदेश में आज 42 लाख 14 हज़ार लाड़ली लक्ष्मी बेटियाँ हो गई हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बेटियों से माता-पिता की हमेशा इज्जत और सम्मान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि माँ को कभी भूलना नहीं। माँ से ही हमारा अस्तित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लाड़ली लक्ष्मी योजना का चमत्कार है कि प्रदेश में बेटियों का लिंगानुपात बढ़कर 956 हो गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान भोपाल के लाल परेड मैदान पर लाड़ली लक्ष्मी उत्सव के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया। राज्य स्तरीय लाड़ली लक्ष्मी उत्सव में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर मौजूद थीं। सांसद श्री वी. डी. शर्मा, विदिशा से कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि डॉक्टर बनने में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 7-8 लाख रूपए फीस लगती है। मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम या किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने पर लाड़ली लक्ष्मी की पूरी फीस राज्य सरकार भरेगी। कक्षा 12 वीं पास कर कॉलेज में प्रवेश लेने वाली लाड़ली लक्ष्मियों को 25 हजार रूपए दो किस्तों में अलग से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बच्चियों से फीस की चिंता न कर पढ़ाई की चिंता करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी लाड़लियों की आँखों में कभी आँसू न आएँ यही मेरी कामना है। हर साल 2 मई से 12 मई तक लाड़ली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि व्यक्ति जैसा सोचना है वैसा बन जाता है। बेटियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर माता-पिता, देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमने लाड़ली ई-संवाद एप बनाया है, जिससे जरूरत पड़ने पर बेटियाँ मुझसे सीधे संवाद कर सकें। यह लाड़ली बेटियों की जिंदगी बदलने का प्रयास है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिस पंचायत में लाड़लियों का सम्मान होगा, जहाँ एक भी बाल विवाह नहीं होगा, शाला में लाड़लियों का शत्-प्रतिशत प्रवेश होगा, कोई लाड़ली कुपोषित नहीं होगी और कोई भी बालिका अपराध घटित नहीं होगा, ऐसी ग्राम पंचायतों को लाड़ली लक्ष्मी पंचायत घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रदेश आगे बढ़े, मेरी लाड़लियाँ आगे बढ़ें। प्रदेश की लाड़ली लक्ष्मियों से कहना चाहता हूँ कि चिंता मत करना, मामा तुम्हारे साथ है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम के शुभारंभ में कन्याओं का पूजन और दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में लगभग 7,500 लाड़ली लक्ष्मी बेटियाँ उपस्थित थी। सभी जिले, विकासखंड, ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों से भी लाड़ली लक्ष्मियाँ और जन-प्रतिनिधि वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में मंच पर पहुँचने से पहले लाड़ली लक्ष्मियों से मिले और पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाड़ली ई-सवांद एप का लोकार्पण भी किया। जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित लाड़ली पुस्तिका एवं लाड़ली लक्ष्मी योजना के ब्रोशर का विमोचन किया। जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार लाड़ली लक्ष्मी योजना पर केन्द्रित लघु फिल्म की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम लाड़ली लक्ष्मी बालिका ने स्वागत उदबोधन दिया। अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास श्री अशोक कुमार शाह ने कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तीन लाड़ली बालिकाओं को प्रतीकात्मक रूप से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस वितरित किए। उन्होंने लाड़ली गीत का विमोचन भी किया। तीन लाड़ली लक्ष्मियों को विशेष उपलब्धि के लिये पुरस्कार वितरित किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान और लाड़ली लक्ष्मियों ने रंगबिरंगे गुब्बारे आकाश में छोड़े।

भू-अधिकार ऋण पुस्तिका ऑनलाइन प्राप्त करें किसान : गोविंद सिंह राजपूत

विभाग की ई-तकनीक का फायदा उठाएँ किसान और आम जन-मानस - राजस्व मंत्री श्री राजपूत

भोपाल : राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि किसानों और आम जनता को भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्राप्त करने के लिए अब पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आम जनता की सुविधा के लिये भू-अधिकार ऋण पुस्तिका को ऑनलाइन कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी भू-अधिकार ऋण पुस्तिका को नजदीकी कियोस्क सेंटर अथवा कॉमन सर्विस सेंटर या स्वयं के एन्ड्रायड मोबाइल से निर्धारित शुल्क 10 रूपये अदा कर ले सकता है।

मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि प्रदेश की जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग ई-तकनीक को बढ़ावा दे रहा है, ताकि किसानों एवं आमजन को तहसील एवं पटवारी के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि वर्षों पूर्व आमजन और किसानों को अपने खाते की नकल पाना कठिन कार्य था। जन-मानस की परेशानी को ध्यान में रखते हुए आजादी के 70 साल बाद राजस्व विभाग के नियमों में बदलाव कर जन-सुविधा से जुड़े अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं।

श्री राजपूत ने जनता से अपील करते हुए कहा कि राजस्व महकमे द्वारा सुविधाजनक रूप से किए गए बदलाव का ई-तकनीक के माध्यम से लाभ उठाएँ और परेशानी से बचें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों या आमजन को उनके खाते की खसरा, वी-1 एवं ऋण-पुस्तिका की प्रति वाट्सएप पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। श्री राजपूत ने कहा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार लगातार जन-हितैषी निर्णय ले रही है, ताकि राजस्व अभिलेखों की प्रति जनता को सहजता से उपलब्ध हो सके।

सभी जिलों का भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन

राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब मध्यप्रदेश के किसी भी जिले से संबंधित भूमि रिकॉर्ड को जनता ऑनलाइन घर बैठे देख सकती है।

अब जन-मानस को सरकारी कार्यालयों में छोटी-छोटी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए बार-बार नहीं जाना पड़ेगा। श्री राजपूत ने कहा कि जनता मध्यप्रदेश भू-अभिलेख पोर्टल के माध्यम से खसरा-खतौनी की नकल, भू-अभिलेख का रिकॉर्ड, आबादी सर्वे का रिकॉर्ड, बंधक भूमि की स्थिति, बंदोबस्त अधिकार अभिलेख, बंदोबस्त निस्तार पत्रक की स्केन प्रति, जमा बंधी नकल, खेत का नक्शा, विवादित भूमि का विवरण आदि ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

आलू बीज उत्पादन की एरोपॉनिक विधि का प्रदेश के साथ अनुबंध, ग्वालियर में बनेगी लैब

किसानों को प्रमाणित बीज़ समय पर उपलब्ध कराने सरकार प्रतिबद्ध - केंद्रीय मंत्री श्री तोमर

एरोपॉनिक विधि म.प्र. के आलू बीज की मांग को पूरा करेगी - राज्य मंत्री श्री कुशवाह

भोपाल : केंद्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य एवं म.प्र. के उद्यानिकी, खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाह के विशेष आतिथ्य में विषाणु रोग रहित आलू बीज उत्पादन के लिए एरोपॉनिक विधि का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और मध्यप्रदेश सरकार के साथ दिल्ली में अनुबंध हुआ। अनुबंध के अनुसार ग्वालियर में प्रदेश की पहली एरोपॉनिक तकनीक आधारित लैब स्थापित होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला ने हवा में आलू के बीज उत्पादन की यह अनूठी तकनीक विकसित की है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि किसानों को फसलों के प्रमाणित बीज समय पर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी कड़ी में आईसीएआर के संस्थानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में नई तकनीकों का विकास किया जा रहा है।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित विषाणु रोग रहित बीज आलू उत्पादन की एरोपॉनिक विधि से बीज आलू की उपलब्धता देश के कई भागों में किसानों के लिए सुलभ की गई है। आज मध्यप्रदेश के उद्यानिकी विभाग को इस तकनीक का लाइसेंस देने के लिए अनुबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि यह नई तकनीक आलू के बीज की आवश्यकता को पूरा करेगी। राज्य के साथ ही देश में भी आलू के उत्पादन में वृद्धि करेगी। आलू विश्व की सबसे महत्वपूर्ण गैर-अनाज फसल है, जिसकी वैश्विक खाद्य प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने श्रेष्ठ अनुसंधान के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कृषि के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अनेक योजनाओं पर मिशन मोड में काम कर रही है।

मध्यप्रदेश के खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर दिल्ली अनुबंध करने आये हैं। उन्होंने कहा कि एरोपॉनिक तकनीक आलू बीज की जरूरत को काफी हद तक पूरा करेगी। किसानों की आय को दोगुना करने में यह तकनीक कारगर भूमिका निभायेगी। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमेप पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश आलू का छठा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रदेश का मालवा क्षेत्र आलू उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मध्यप्रदेश आलू प्र-संस्करण के लिए आदर्श राज्य के रूप में उभरा है। प्रदेश में प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्र इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, भोपाल तथा प्रदेश के अन्य छोटे क्षेत्र छिंदवाड़ा, सीधी, सतना, रीवा, राजगढ़, सागर, दमोह, छिंदवाड़ा, जबलपुर, पन्ना, मुरैना, छतरपुर, विदिशा, रतलाम एवं बैतूल हैं। प्रदेश में उच्च गुणवता वाले बीज़ की कमी हमेशा से समस्या रही है, जिसका हल किया जा रहा है। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर का आभार माना और उनको धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की चिंता करते हुए योजनाओं को गंभीरता से अमल में ला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों को अनेक सौगातें दी है।

प्रदेश के उद्यानिकी आयुक्त श्री ई. रमेश कुमार ने कहा कि मध्यप्रदेश को लगभग 4 लाख टन बीज़ की आवश्यकता है, जिसे 10 लाख मिनी ट्यूबर उत्पादन क्षमता वाली इस तकनीक से पूरा किया जाएगा। ग्वालियर में "एक जिला- एक उत्पाद" में आलू फसल का चयन किया गया है।

आईसीएआर के डीजी डॉ. त्रिलोचन महापात्र, डीडीजी-बागवानी डॉ. आनंद कुमार सिंह, मध्यप्रदेश के अपर संचालक उद्यानिकी डॉ. के.एस. किराड़, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के प्रभारी निदेशक डॉ. एन.के. पांडे, एग्रीनोवेट इंडिया की सीईओ डॉ. सुधा मैसूर ने भी संबोधित किया और एरोपॉनिक तकनीक की जानकारी दी। एरोपॉनिक के जरिये पोषक तत्वों का छिड़काव मिस्टिंग के रूप में जड़ों में किया जाता है। पौधे का ऊपरी भाग खुली हवा और प्रकाश में रहता है। एक पौधे से औसत 35-60 मिनिकन्द (3-10 ग्राम) प्राप्त किए जाते हैं। चूँकि, मिट्टी उपयोग नहीं होती, इसलिये मिट्टी से जुड़े रोग नहीं होते हैं।

मध्य प्रदेश में फसल विविधीकरण के लिए सरकार देगी प्रोत्साहन

भोपाल। मध्य प्रदेश में गेहूं-धान के बढ़ते रकबे और उत्पादन में अत्यधिक बढ़ौत्री के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। रसायनिक आदान के अंधाधुंध उपयोग से बिगड़ता पर्यावरण समर्थन मूल्य पर खरीदी के कारण सरकार पर अनावश्यक वित्तीय बोझ, ऐसे अनेक कारणों से निबटने के लिए म.प्र. कृषि विभाग ने फसल विविधीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है।

पात्र फसलें

श्री अजीत केसरी अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन, कृषि विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार इस प्रोत्साहन योजना में गेहूं और धान के अलावा वे फसलें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के दायरे में नहीं आतीं, शामिल रहेंगी। इन 'पात्र फसलों' में उद्यानिकी फसलें-आलू, प्याज, टमाटर एवं अन्य सब्जियां भी सम्मिलित हैं।

योजना में पात्र संस्थाएं

किसानों को परम्परागत फसलों से हटकर विभिन्न और विविध फसलें बोने के लिए प्रेरित करने वाली कम्पनियां, संस्थाएं इस योजना में पात्र होंगी। इसके साथ ही इन संस्थाओं पर किसानों की तकनीकी सलाह देने के साथ-साथ फसल को खरीदने के लिए समझौता करने-कराने का दायित्व होगा। प्रेरक कम्पनियां, संस्थाएं यदि 'पात्र फसल' नहीं खरीदेंगी, इस स्थिति में अन्य कम्पनियों से टाईअप भी करवाएंगी।

योजना में सहायता

इस पूरी विविधीकरण योजना में किसान को प्रेरित करने के लिए कोई आवश्यक कृषि आदान दिया जाता है तो विभाग द्वारा मान्य किया जाएगा।

योजना की प्रक्रिया

फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय राज्य स्तरीय परियोजना परीक्षण समिति का गठन किया है, जिसका सदस्य सचिव संचालक कृषि होगा। इस योजना में 3 वर्ष तक सहायता देने का प्रावधान भी है।

पीएम किसान ई-केवायसी, आधार को बैंक खाता से 31 तक लिंक कराना अनिवार्य

सीहोर : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी पात्र हितग्राहियों को ई-केवायसी एवं आधार को बैंक खाता से लिंक किया जाना अनिवार्य है। जिसकी अंतिम तिथि 31 मई नियत की गई है। हितग्राहियों के लिये ई-केवायसी की सुविधा पीएम किसान पोर्टल पर फार्मर कॉर्नर एवं पीएम किसान एप्प पर निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है, इस सुविधा के माध्यम से आधार लिंक मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से ई-केवायसी की कार्यवाही पूर्ण की जा सकती है।

सीएससी केन्द्रों के माध्यम से भी ई-केवायसी की कार्यवाही हितग्राही द्वारा ओटीपी, बायोमेट्रिक से पूर्ण की जा सकती है। ई-केवायससी एवं आधार को बैंक अकाउण्ट से लिंक किये जाने की अंतिम तिथि 31 मई 2022 नियत की गई है।

पशुओं पर मौसम का प्रभाव

ग्रीष्म ऋतु में जब वातावरण का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, तो पशु प्रजातियों में गर्मी के द्वारा उत्पन्न तनाव होने के कारण पशुओं की शरीर वृद्धि, उत्पादन व प्रजनन क्षमता विपरीत रूप से प्रभावित होने लगती है। सामान्यत: गर्मी तनाव से बचने के लिए पशु प्रजातियों के अनुवांशिक गुण, पशु को विपरीत तापमान के प्रति सहनशील बनाते हैं, परंतु जब तापमान आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तो पशु की दैहिक व दैनिक गतिविधियों में स्वत: ही परिवर्तन होने लगता है और पशु असामान्य महसूस करता है। जिसके कारण पशु की पुर्नउत्पादन प्रक्रिया जैसे मादा गर्भाशय में अंडा न बनना, अंडे का सम्पूर्ण विकास न होना व भ्रूणीय विकास अंडजनन के बाद भ्रूण का विकास न होना आदि तथा नर पशुओं में वीर्य की मात्रा तथा गुणवत्ता में भी गिरावट देखी जाती है।

वैसे तो ग्रीष्मऋतु का प्रभाव लगभग सभी प्रकार के जानवरों पर देखा गया है, परंतु सबसे अधिक प्रभाव गाय, भैंसों पर तथा मुर्गियों पर होता है। यह भैंस के काले रंग, पसीने की कम ग्रंथियों तथा विशेष हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है। जबकि मुर्गियों में पसीने वाली ग्रंथियों की अनुपस्थिति तथा अधिक शरीर तापमान (107 डिग्री फेरानाइट) के कारण होता है।

पशुओं में लू लगने के लक्षण

- पशु गहरी सांस लेता है व हापने लगता है।
- पशु की अत्याधिक लार बहती है।
- पशु छाया ढूंढता है तथा बैठता नहीं है।
- पशु दाना, चारा नहीं खाता है तथा पानी के पास इकट्ठा हो जाता है।
- पशु को झटके आते है तथा अन्त में मृत्यु तक हो जाती है।
- पशु का शरीर छूने में गरम लगता है, तथा गुदा या मलाश्य का तापमान बढ़ जाता है।

गर्मी से बचाव हेतु उपाय

- गर्मी के दिनों में पशुगृह या पशु सार, गर्मी तनाव को कम करने का बहुत महत्वपूर्ण स्त्रोत है। पशुगृह हवादार होना चाहिए जिसमें हवा के आने-जाने का उचित प्रबंधन होना चाहिए। गर्मी से पशुओं को बचाने के लिये पेड़ की छाया उत्तम साधन है। परंतु जहां प्राकृतिक छाया उपलब्ध नहीं है, तो वहां कृत्रिम आश्रय स्थल उपलब्ध कराये जाना चाहिए। पशु गृह के छत की ऊंचाई 12 फीट या उससे अधिक होनी चाहिए।
- पंखों या फव्वारे के द्वारा पशुशाला का तापमान लगभग 15 डिग्री फेरानाइट तक कम किया जा सकता है। पशु शाला के अंदर जो पंखे प्रयोग में लायेजाते है, उनका आकार 36-48 इंच और जमीन से लगभग 5 फीट ऊंची दीवार पर 30 डिग्री एंगल पर लगाएं।
- वाष्पीकरण ठंडा विधि से पंखे, कूलिंग पेड़ और पंप द्वारा जो कि पानी को प्रसारित व प्रवाहित करके दवाब के साथ-साथ पानी की छोटी-छोटी बूंदों में बदलकर पशुओं के ऊपर छिडक़ता है, जिससे गर्मी के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
- पशुशाला को कूलर लगाकर भी ठंडा किया जा सकता है।
- एक कूलर लगभग 20 वर्गफुट की जगह को बहुत अच्छा ठंडा कर सकता है।
- पशुशाला के आसपास यदि तालाब हो तो पशु को तालाब के अंदर नहलाने से पशु का शरीर का तापमान कम हो जाता है। तालाब बनाने पर तालाब की लंबाई 80 फीट, चौड़ाई 50 फीट तथा गहराई 4-6 फीट होना चाहिए।

गर्मी का गाय, भैंसों पर प्रभाव

- गर्मी के कारण पशु की चारा व दाना खाने की क्षमता घट जाती है।
- पशु की दुग्ध उत्पादन क्षमता घटती है।
- मादा पशु समय से गर्मी या ऋतुकाल में नहीं आती है।
- गाय, भैंसों के दूध में वसा तथा प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे दूध की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- गर्भधारण क्षमता घट जाती है।
- मादा पशु बार-बार गर्मी में आती है।
- मादा में भ्रूणीय मृत्यु दर बढ़ जाती है।
- पशु का व्यवहार असामान्य हो जाता है। नर पशु की प्रजनन क्षमता घट जाती है।
- नर पशु से प्राप्त वीर्य में शुक्राणु मृत्यु दर अधिक पाई जाती है।
- नर व मादा पशु की परिपक्वता अवधि बढ़ जाती है।
- बच्चों की अल्प आयु में मृत्यु दर बढ़ जाती है।

गर्मी में दुधारू पशुओं का बचाव कैसे करें

किसान के लिए पशुधन आवश्यक ही नहीं अपितु परमावश्यक धन है। उनकी जीवनशैली, दिनचर्या, खानपान व सम्पत्ति पशुधन के चारों तरफ घूमती है। सिकुड़ती ज़मीन, बढ़ते परिवारों के खर्च किसान के लिए यह और भी आवश्यक कर देते हैं कि वह अपने पशुधन से अधिकतम आय व लाभ प्राप्त कर सकें। इसके लिए पशु को अधिक गर्मी व अन्य दूषित वातावरण से पशुधन को बचाकर अच्छे व्यवहार के साथ रखना आवश्यक है ताकि पशु की ऊर्जा गर्मी से लडऩे में व्यर्थ न हो और यह ऊर्जा आदर के साथ उत्पादन बढ़ाने में लगे। गर्मी के मौसम में वातावरण का तापमान काफी बढ़ जाता है। कई बार तो तापमान 50 डिग्री सेन्टीग्रेड तक चला जाता है जो कि पशु के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। हम जानते है कि गाय व भैंस के शरीर का सामान्य तापमान 101.5 डिग्री फारेनहाईट व 98.3 – 103 डिग्री फारेनहाईट सारे साल रहता है। पशुओं के अच्छे उत्पादन के लिए सामान्यत: 5 से 25 डिग्री सेन्टीग्रेड का तापमान बड़ा अनुकूल है। इस तापमान से अधिक और कम तापमान से बचाव के लिए प्रबन्ध करना बहुत आवश्यक है। हम जानते हैं कि गर्मी के मौसम में प्रतिकूल तापमान से प्रभावित होने के कारण पशुओं का दूध उत्पादन कम हो जाता है। अगर हम

अपने पशुओं का ठीक ढंग से हरे चारे व संतुलित आहार का प्रबन्ध, पानी व अन्य देखभाल ठीक करेंगें तो गर्मी के मौसम में अपने दुधारू पशुओं से पूरा उत्पादन ले सकते हैं।

हरे चारे व सन्तुलित आहार का प्रबन्ध

हम जानते हैं कि गर्मी के मौसम में हरे चारे की कमी आ जाती है विशेष तौर से मई व जून के महीनों में, अगर हमें ठीक प्रकार से फसल चक्र बनाकर हरे चारे की व्यवस्था करेंगें तो गर्मी के मौसम में भी हम अपने पशुओं के लिए हरे चारे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर हम मार्च अप्रैल के महीने में अधिक बरसीम को हम 'हे' बनाकर ऊपर लिखित कमी वाले समय में खिलाकर हरे चारे की पूर्ति कर सकते हैं।

संतुलित आहार

संतुलित आहार वह आहार होता है जिसके अन्दर प्रोटीन, ऊर्जा, खनिज तत्व व विटामिन इत्यादि उपलब्ध हों तथा 100 किलो संतुलित आहार इस प्रकार से बनाएँ – गेहूं, मक्का व बाजरा इत्यादि अनाज 32 किलोग्राम, सरसों की खल 10 किलोग्राम, बिनौले की खल 10 किलोग्राम, दालों की चूरी 10 किलोग्राम, चौकर 25 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम व साधारण नमक एक किलोग्राम लें। इसके साथ-साथ गर्मी के मौसम में पशुओं को प्रोटीन की मात्रा यानि की पशु आहार के अन्दर खलें जैसे सरसों की खल इत्यादि की मात्रा 30 से 35 प्रतिशत बढ़ा दें तथा इस प्रकार हम गर्मी के मौसम में हरे चारे व संतुलित आहार तथा विशेष प्रोटीनयुक्त चारा खिलाने से अपने पशुओं को गर्मी से बचाकर दूध उत्पादन बनाकर रख सकते हैं। पानी गर्मी के मौसम में पशु अपने शरीर की गर्मी को कम करने के लिए पानी की अधिक मात्रा ग्रहण करता है तथा शरीर के अतिरिक्त तत्व पसीने के द्वारा, पेशाब व गोबर के द्वारा व अन्य अंगों से बाहर निकालता है तथा अपने शरीर को तन्दरूस्त रखता है। क्योंकि पशु शरीर के अन्दर 65 प्रतिशत पानी होता है जो कि पशु की सारी क्रियाएं सुचारू रूप से च्लाता है। गर्मी के मौसम में अक्सर पशु शरीर के अन्दर पानी की कमी आ जाती है। इसके लिए हमें विशेष ध्यान रखकर पशु के शरीर की पानी की पूर्ति करें। हम जानते हैं कि दूध के अन्दर पानी की मात्रा तकरीबन 87 प्रतिशत होती है। अगर पशु के शरीर के अन्दर पानी की कमी होगी तो दूध उत्पादन निश्चित रूप से कम हो जाएगा। वैसे पशु को पानी की जरूरत मुख्य रूप से तीन आधारों पर निर्भर करती है:-

दूध उत्पादन की जरूरत

पशु शरीर के हर 100 किलोग्राम वजन पर तकरीबन 5 लीटर पानी की जरूरत होती है। अत: पशुपालक भाईयों को सलाह दी जाती है कि पशु के शरीर का वजन का हिसाब लगाकर पानी की पूर्ति करें। तकरीबन हमारी दुधारू भैंसों का वजन 500 से 600 किलोग्राम प्रति भैंस होता है। इसके हिसाब से हिसाब लगाकर पानी की पूर्ति करें।

दुधारू पशु को एक किलोग्राम दूध पैदा करने के लिए तकरीबन एक किलोग्राम पानी की जरूरत होती है। इसलिए आप अपने पशु का दूध उत्पादन का हिसाब लगाकर उससे भी अधिक पानी की पूर्ति करें। इस प्रकार खिलाए चारों की किस्म (सूखा-हरा) का हिसाब लगाकर पानी की पूर्ति करें। क्योंकि अगर हमने बरसीम खिलाई है तो उससे पशु को तकरीबन 70 से 80 प्रतिशत पानी मिलता है, इसी प्रकार अगर हरी ज्वार खिलाई है तो तकरीबन 55 से 60 प्रतिशत पानी मिलता है। इसलिए ऊपर लिखित आधार को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि गर्मी के मौसम में अच्छा दूध उत्पादन लेने के लिए अच्छे दूधारू भैंस जिसका दूध उत्पादन करीबन 15 से 20 किलोग्राम प्रतिदिन हो उसे 70 से 80 लीटर स्वच्छ व ठंडा पानी गर्मी के मौसम में 24 घण्टे में पिलाने से हम अपने दूधारू पशुओं का दूध उत्पादन बनाकर रख सकते हैं।

फसल सुरक्षा : लंबे समय तक अनाज को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके

अनाज संरक्षण की विधियां और इससे होने वाले लाभ

देश में इस समय गेहूं की कटाई का काम चल रहा है। ऐसे में किसान चाहते हैं कि वे अपनी उपज का सुरक्षित भंडारण कर सकें। हालांकि सरकार की ओर से किसानों के लिए अनाज भंडारण के लिए सरकारी भंडार गृह खोले गए हैं जिसमें कुछ शुल्क देकर किसान भाई अपनी उपज का भंडारण कर सकते हैं। लेकिन सभी किसान ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाते है, खास कर छोटे किसान। और ऐसा नहीं करने पर उन्हें फसल खराब होने का डर बना रहता है और इसके चलते वे कई बार अपनी फसल औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को अनाज सुरक्षा के दो आसान तरीके बता रहे हैं जिससे वे अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकेंगे।

लंबे समय तक अनाज सुरक्षित रखने से किसानों को क्या लाभ

कई किसान इस उद्देश्य से अपनी उपज का लंबे समय तक सुरक्षित भंडारण करते हैं ताकि उन्हें बाजार में उपज का उचित मूल्य मिल सके। कई बार मंडी की खबरों में आता है कि अमुक दिन सरसों का भाव बढ़ गया है या फिर कम हो गया है। इस भाव के उतार-चढ़ाव की स्थिति ही किसानों के लाभ और हानि का निर्धारण करती है। यदि बाजार में उपज का दाम बढ़ गया है तो किसान को लाभ होता है। और इसके विपरित बाजार में उपज का भाव कम चल रहा है तो किसान को हानि उठानी पड़ती है। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि बाजार में उपज का भाव इतना गिर जाता है कि किसान को अपनी उपज की लागत तक निकालना भारी पड़ जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उपज का भंडारण करना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि उपज का उचित मूल्य किसान को मिल सके।

भंडारण की सही जानकारी के अभाव में होता है नुकसान

अनाज को चूहों, कीटों, नमी, फफूंद आदि से उपज को नुकसान होता है। अनाज भंडारण की सही जानकारी नहीं होने से प्राप्त उपज में कमी होने लगती है। यदि अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हो तो आपको इसके किए भंडारण की वैज्ञानिक विधि को अपनाने की आवश्यकता होगी। फसलों की कटाई के बाद सबसे जरूरी काम अनाज भंडारण का होता है। अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए वैज्ञानिक विधि अपनाने की जरूरत होती है, जिससे अनाज को लंबे समय तक चूहे, कीटों, नमी, फफूंद आदि से बचाया जा सके। भंडारण की सही जानकारी न होने से 10 से 15 प्रतिशत तक अनाज नमी, दीमक, घुन, बैक्टीरिया द्वारा नष्ट हो जाता है।

गोदाम में अनाज संग्रहण के लिए किन बातों का रखें ध्यान

- अनाज को रखने के लिए जिस कमरे या गोदाम को उपयोग में लाया जा रहा है। उसकी अच्छी तरह से साफ-सफाई करनी चाहिए।
- दीमक और पुराने अवशेष आदि को बाहर निकालकर जलाकर नष्ट कर देना चाहिए।
- दीवारों, फर्श एवं जमीन आदि में यदि दरार हो तो उसे सीमेंट, ईट से बंद कर दें।
- टूटी दीवारों आदि की मरम्मत करा देनी चाहिए।

अनाज स्टोर करने से पहले ये रखें सावधानियां

- अनाज को भंडार गृह में स्टोर करने से पहले अनाजों को अच्छी तरह से साफ-सुथरा कर धूप में सुखा लेना चाहिए, जिससे कि दानों में 10 प्रतिशत से अधिक नमी न रहने पाए।
- अनाज में ज्यादा नमी रहने से फफूंद एवं कीटों का आक्रमण अधिक होता है। अनाज को सुखाने के बाद दांत से तोडऩे पर कट की आवाज करें तो समझना चाहिए कि अनाज भंडारण के लायक सूख गया है।
- इसके बाद अनाज छाया में रखने के बाद ठंडा हो जाने के बाद ही भंडार में रखना चाहिए।

भंडारण के लिए तैयार करें लकड़ी और तख्ते का मंच

अनाज से भरे बोरे को भंडार गृह में रखने के लिए फर्श से 20 से 25 सेमी की ऊंचाई पर बांस या लकड़ी के तख्ते का मंच तैयार करना चाहिए, जो दीवार से कम-से-कम 75 सेमी की दूरी पर हो। बोरियों के छल्लियों के बीच भी 75 सेमी खाली स्थान रखना फायदेमंद होता है। गोदाम में पक्षियों एवं चूहों के आने-जाने के रास्ते को बंद कर देना चाहिए।

अनाज और दालों के सुरक्षित भंडारण के कुछ पारंपरिक तरीके

अनाजों व दालों का भंडारण कुछ पारंपरिक अन्न भंडारण के तरीके जैसे आनाजों व दालों के कड़वा तेल लगाना, राख मिलाना, नीम, लहसुन व करंज के पत्ते कोठी में बिछाना, सूखे हुए लहसुन के डंठल रखना आदि। अनुसंधानों द्वारा यह पाया गया कि परंपरागत तरीके से आनाज व दालों में 10-20 प्रतिशत तक राख मिलाने से वो खराब नहीं होते पर आवश्यक है कि राख को छानकर व सुखा कर ही डाला जाय। राख की रगड़ खाकर कीड़े मर जाते और दोनों के बीच की जगह जहां हवा हो सकती है, वहां राख आ जाने से हवा नहीं रहती है। इस प्रकार राख मिलाना लाभप्रद होता है।

भंडारण करने से पहले यह इन बातों का रखें ध्यान

- अनाज भरे बोरे को छल्लियों या अन्न के ढेर को प्रधूमित करने के लिए एल्मुनियम फॉस्फाइड का पाउच आवश्यकतानुसार रखकर पॉलीथीन चादर से अच्छी तरह ढक कर उसके किनारे को सतह के साथ गीली मिट्टी से वायुरुद्ध कर देना चाहिए।
- चूहों से बचाने के लिए एक ग्राम जिंक फॉस्फाईड और उन्नीस ग्राम सत्तू या आटा में थोड़ा सरसों तेल मिलाकर एवं लगभग 10 ग्राम की गोली बनाकर चूहों के आने-जाने के रास्ते पर गिनती में रख देना चाहिए। खुले हुए अनाज पर कीटनाशी नहीं रखना चाहिए, चूहा शंकालु प्रवृत्ति का होता है। इसलिए बदल-बदल कर विषाक्त चारा, चूहे-दानी एवं टिकिया को रखना चाहिए। दवा अनाज में देने के बाद हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लेना चाहिए।
- भंडारण में पुराना आनाज एवं भूसा इत्यादि को निकाल कर एक महीने पहले सफाई कर चूहों द्वारा किए गए छेद एवं अन्य टूट-फूट की मरम्मत कर नीम की पत्ती का प्रधुमन करके अच्छी तरह से भंडारण को बंद कर दें, जिसमें छुपे हुए भंडारण कीट नष्ट हो जाए एवं अन्य भंडारण बोरी को खौलती नीम की पत्ती वाले पानी में शोधित कर अच्छी तरह सुखा ले।
- अन्न का भंडारण करते समय हवा के रुख को अवश्य ध्यान रखे अगर पुरवा हवा चल रही हो, तब अन्न का भंडारण न करें।
- अनाज भंडारण में नीम की पत्ती का प्रयोग करते समय नीम पत्ती सूखी होनी चाहिए। इसके लिए नीम पत्ती को भंडारण से 15 दिन पहले किसी छायादार स्थान पर कागज पर रख कर सुखा ले उसके बाद अन्न की बोरी में रखे।

भंडारण गृह के चयन में ये बरतें सावधानियां

- अनाज व दालों को सुरक्षित भंडारण के लिए वैसे भंडार गृह का चयन करना चाहिए, जहां सीलन (नमी) न हो एवं चूहों से अन्न का बचाव किया जा सके।
- भंडार-गृह हवादार हो एवं जरूरत पड़ने पर वायुरुद्ध भी किया जा सके।
- अनाज भंडारण से पूर्व पक्का भंडार गृह एवं धातु की कोठियों को साफ-सुथरा कर लेना चाहिए।
- भंडार गृह को कीटमुक्त करने के लिए मेलाथियान 50 प्रतिशत का पानी में 1:100 में बने घोल को दीवारों एवं फर्श पर प्रति एक सौ वर्ग मीटर में तीन लेयर घोल की दर से छिडक़ाव करना चाहिए।

अनाज भरने से पूर्व बोरियों को करें रोगाणुमुक्त

- बोरियों में अनाज भर कर रखने के पहले इन बोरियों को 20-25 मिनट तक खौलते पानी में डाल देना चाहिए। इसके बाद धूप में अच्छी तरह सूखा देना चाहिए।
- इसके बाद छिडक़ाव के लिए बने मालाथियान 50 प्रतिशत के घोल में बोरियों को डुबाकर फिर बाहर निकालकर सुखा लेना चाहिए। ठीक से सूख जाने के बाद ही उसमें अनाज भरना चाहिए।

जैविक खेती को बढ़ावा देने हर संभव करेंगे उपाय

सीहोर : किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने कहा हैं कि जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार सभी संभव उपाय करेगी। कृषि विभाग ने कहा हैं कि मध्यप्रदेश की खेती- किसानी में बढ़ते पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के उपयोग को रोकने के जैविक खाद निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए सरकार पशुपालन विभाग के साथ मिलकर एक नए मॉडल को विकसित कर लागू करेगी। कृषि विभाग ने कहा कि गौशालाओं में निजी भागीदारी भी सुनिश्चित करने के प्रयास करेंगे, जिससे जैविक खाद निर्माण में और अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके। पशुपालन विभाग के साथ कृषि विभाग के वैज्ञानिक अनुसंधान कर प्रदेश की गौशालाओं को आत्म-निर्भर बनाएंगे। निजी सहभागिता से चलने वाली गौशालाओं की सतत निगरानी की जाएगी, जिससे गौशालाओं का व्यवस्थित संचालन हो। गोबर और गोमूत्र का उपयोग हो और किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद मिल सके।

देश का पहला ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण भोपाल में

प्रधानमंत्री श्री मोदी के विजन से समाज के सभी वर्गों के उत्थान का हो रहा प्रयास : मुख्यमंत्री श्री चौहान

म.प्र. में जनजातीय वर्ग के विकास का चल रहा है अभियान

मध्यप्रदेश से शुरू हुई पायलेट आधार पर संसदीय संकुल परियोजना

प्रशिक्षण कार्यक्रम में 6 राज्य के 15 जिला के युवक शामिल

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनजातीय युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाएगा। एक तरफ जहाँ जनजातीय वर्ग के युवाओं को रोजगार चाहिए, वही ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी दक्षता वाले इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मेसन, वाहन मैकेनिक आदि की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से जनजातीय युवाओं के लिए संसदीय संकुल परियोजना में ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम सार्थक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे थे। मध्यप्रदेश सहित छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उड़ीसा के जिले प्रथम चरण में प्रायोगिक परियोजना के लिए चुने गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी मैन ऑफ आयडियाज़ हैं। उनके दृष्टिकोण और सबका साथ-सबका विकासकी नीति के अनुरूप समाज के सबसे पिछड़ें वर्गों को बराबरी पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनजातीय वर्ग की जिंदगी बदलने का अभियान संचालित किया जा रहा है। पेसा एक्ट लागू करने, वन ग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने, जनजातीय वर्ग के बच्चों को अध्ययन की सुविधाएँ देने और ग्रामीण इंजीनियर तैयार करने की योजना में उन्हें महत्त्व देने के कदम उठाए गए हैं। ग्रामों में कार्य के लिए लाखों लोगों की जरूरत है। जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन और यंत्रों के संधारण के लिए युवा जनजातीय वर्ग को लाभान्वित किया जा रहा है। कौशल प्रशिक्षण से उन्हें रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। हुनर होने से काम मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन भी रूकेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनजातीय इलाकों में रोजगार के सीमित अवसर होते हैं। इस वजह से युवाओं को बाहर जाने की विवशता होती है। अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिल जाने से स्थानीय सामाजिक-आर्थिक ढाँचा भी मजबूत होता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने

इस दृष्टिकोण से ही 40 सासंदों के साथ मुम्बई संगोष्ठी में गहन विचार-विमर्श किया था। इसके बाद विशेषज्ञों और अनुसूचित जनजाति संगठनों से चर्चा की गई। लोकसभा और राज्यसभा के चयनित सांसदों ने 15 राज्यों के 49 समूह चुने। युवाओं को दो माह की अवधि के प्रशिक्षण से स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार के साथ समाज खड़ा हो, तभी हमारे कल्याणकारी कार्यक्रम ज्यादा सफल होंगे। प्रदेश में स्वच्छता के क्षेत्र में ऐसा हुआ है। साथ ही कोरोना से लड़ाई में भी यह बात सिद्ध हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में ग्राम और शहरों के गौरव दिवस मनाने के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। गाँव को स्वच्छ रखने, बिजली के अपव्यय को रोकने, आँगनवाड़ी केंद्रों के संचालन में किसानों द्वारा दिया जा रहा सहयोग भी देखने को मिल रहा है। आम नागरिक भी आँगनवाड़ियों में अनाज का सहयोग देकर कुपोषण से बच्चों को बचाने के कार्य में सक्रिय हुए हैं। ग्राम को नशा मुक्त बनाने की पहल अनेक स्थान पर की गई है। नागरिक पौधा-रोपण कर रहे हैं। वृहद स्तर पर वृक्षा-रोपण से पर्यावरण सुधार के कार्य हो रहे हैं। ग्रामीण इंजीनियर तैयार करने और मध्यप्रदेश में भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण का कार्य हुआ है। आज ऐसी अभिनव योजना को प्रारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से युवकों को मिलने वाली सहायता की जानकारी भी दी।

कार्यक्रम के विशेष अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री श्री बीएल संतोष ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, तभी वे पलायन से बचेंगे। आज शिक्षकों, चिकित्सकों और अन्य पदों पर कार्य कर रहे लोग जनजातीय क्षेत्रों में कार्य की मन: स्थिति बनाने लगे हैं। यह जनजातीय वर्ग के हित में भी है। जनजातीय युवाओं से काफी आशाएँ हैं। तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर वे रोजगार का सशक्त माध्यम चुने, जो जनजातीय समाज की बेहतरी के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के मुताबिक जनजातीय वर्ग के लिये तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी।

(पृष्ठ 1 का शेष)

किसानों के हित में रबी उपार्जन....

किसानों की उपज की सफाई एवं ग्रेडिंग को अनिवार्य किया गया है। किसानों को उनकी उपज के भुगतान को पारदर्शी बनाने के उदेश्य से जेआईटी/ पीएफएमएस के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा।

17 लाख नए परिवार शामिल

खाद्य मंत्री श्री सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 17 लाख नए परिवारों के 62 लाख नए सदस्यों को हितग्राही के रूप में खाद्यान्न वितरित किया गया। इससे बेघर और बेसहारा श्रेणी में 2623 परिवारों के 8929 सदस्यों को लाभ मिला। इस वर्ष एनएफएसए और पीएमजीकेएवाय में जनवरी में 94 प्रतिशत से अधिक खाद्यान्न का आवंटन एवं वितरण किया गया।

19 लाख एमटी गेहूँ का हुआ उपार्जन

प्रमुख सचिव खाद्य श्री किदवई ने बताया कि इस वर्ष 4 हजार 225 केन्द्रों पर 9 मई तक 19 लाख 81 हजार 506 मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया है। इस वर्ष 19 लाख 76 हजार 628 किसानों ने उपज विक्रय के लिए पंजीयन कराया, जो विगत वर्ष का 80 प्रतिशत है। इस वर्ष समर्थन मूल्य 2015 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रूपये निर्धारित किया गया था। विगत वर्ष 17 लाख 16 हजार 671 किसानों ने अपनी उपज का विक्रय किया था।

संचालक खाद्य श्री दीपक सक्सेना, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम श्री तरूण पिथौड़े एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कृषि मंत्रालय व यूएनडीपी के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व केसीसी के संबंध में हुआ समझौता - कृषि मंत्री श्री तोमर

मुरैना : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) एवं किसान क्रेडिटकार्ड–संशोधित ब्याज सहायता योजना (केसीसी-एमआईएसएस) के संबंध में आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्रसिंह तोमर की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

कार्यक्रम में श्री तोमर ने कहा कि देश के छोटे किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह समझौता किया गया है, जिससे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) का समर्थन मिलने से उन्हें फायदा होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किसान हितैषी अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनका लाभ सभी पात्र किसानों को पारदर्शिता से पहुंचाना सुनिश्चित हो रहा है। केंद्रीय योजनाओं में बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं है।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि बीते तीन साल से यूएनडीपी के साथ यह साझेदारी चल रही है, जिसके अच्छे परिणाम के कारण साझेदारी को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया हैं।इससे किसानों को कृषि संबंधित वित्तपोषण तथा फसल बीमा के महत्व को समझने एवं उपयोग करने में भी सहायता होगी।उन्होंने कहा कि पीएमएफबीवाई देश के किसानों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच है, जिसका बड़ी मात्रा में किसानों को लाभ मिल रहा है। अभी तक किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 21 हजार करोड़ रुपये जमा कराए, जबकि फसलों के नुकसान की भरपाई के रूप में उन्हें 1.15 लाख करोड़ रु. का क्लेम दिया गया है। सरकार चाहती है कि कोई भी पात्र किसान क्लेम पाने से वंचित नहीं रहे, सभी बीमित किसानों को मुआवजा मिलें। किसानों के हित में पीएमएफबीवाई को सरल भी किया गया है।

श्री तोमर ने कहा कि केसीसी का लाभ भी छोटे किसानों को मिल रहा है और किसानों को अभी तक लगभग 16 लाख करोड़ रु. लोन के रूप में दिए गए हैं। कोरोना के संकटकाल में दो करोड़ से ज्यादा केसीसी बनाए गए हैं, कुल मिलाकर लक्ष्य यह है कि छोटे से छोटे किसानों को भी इसका लाभ मिलें। पशुपालकों व मत्स्यपालकों को भी केसीसी योजना से जोड़कर लाभ दिया जा रहा है।

एमओयू पर पीएमएफबीवाई के सीईओ श्री रितेश चौहान और यूएनडीपी की निवासी प्रतिनिधि सुश्री शोकोनोडा ने हस्ताक्षर किए। एमओयू के अनुसार, यह साझेदारी कृषि ऋण और फसल बीमा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करेगी एवं मौजूदा राष्ट्रीय और राज्य संस्थानोंको सूचना, शिक्षा, संचार सहायता एवं क्षमता विकास प्रदान करेगी। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी व कृषि सचिव श्री मनोज अहूजा भी उपस्थित थे।

नेशनल डेयरी प्लान फेज–2

नस्ल सुधार, दूध उत्पादन बढ़ाने पर हो चुका है काम
दुग्ध संघ का नेटवर्क बढ़ेगा, बदलेगी मार्केटिंग की रणनीति

भोपाल। केन्द्र सरकार, मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में नेशनल डेयरी प्लान (एनडीपी) का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। वर्ल्ड बैंक की फंडिग से पहला प्लान 2012–13 में काम शुरू हुआ और 2018–19 में समाप्त हुआ। इसमे सीमन केन्द्र सुदृढ़ीकरण ,प्रोजेनी टेस्टिंग, पेडेग्री, बल्क मिल्क कूलर राशन बैलेंसिंग और फॉडर डेव्लपमेंट जैसे प्रोजेक्ट पर फोकस किया गया। इसके चलते दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने में काफी मदद मिली। इसी को देखते हुए दूसरा चरण चलाया जाएगा। प्रदेश में इस बार मुख्य रूप स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (एमपीएससीडीएफ) के अंतर्गत सहकारी दुग्ध संघों के नेटवर्क को गांव–गांव तक पहुॅचाने, सांची के उत्पादों की संख्या बढ़ाने और मार्केटिंग कर आम लोगों के घरों तक पहुंचना शामिल हैं। कुछ प्रोजेक्ट म0प्र0 राज्य डेयरी एवं पशुधन कुक्कुट विकास निगम अपने हाथ में लेगा जिनके लिए राज्यभर में स्थित उसके सेंटर्स पर इकाईयां लगाई जाएगी।

पहले चरण में प्रयास

केन्द्र का लक्ष्य देशी नस्ल वाले उच्च श्रेणी के गो व भैंसवंशीय नर के फ्रोजन सीमन से राज्यों में कृत्रिम गर्भाधान करवाने पर रहा। बुल प्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत बैलों की संख्या पर नियंत्रण का प्रयास शुरू हुआ। अच्छी नस्ल की बछिया से दूध उत्पादन बढ़ा।

अब यह होगा

दूध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लैब से लेकर प्लांट तक के लिए रणनीति रहेगी। मार्केटिंग को आक्रामक किया जाएगा। अंचल से कलेक्शन और लोगों तक उत्पाद वितरण की व्यवस्था मजबूत होगी। अभी प्रदेश की कुल आबादी में से 17% तक ही उत्पाद पहुॅच पा रहे हैं। एन डी पी का दूसरा चरण भी पहले की तरह मध्य प्रदेश के लिए क्रांतिकारी साबित होगा। वर्ल्ड बैंक से पिछली बार 5 करोड़ रूपये की मदद मिली थी। दूसरे चरण के लिए भोपाल में 5 मई को बैठक हो चुकी हैं। इसमें एनडीडीबी,बर्ल्ड बैंक पशुपालन एवं डेयरी विभाग, म.प्र. दुग्धसंघ व सहकारी समितियां कुक्कट विकास निगम आदि के अधिकारी मौजूद रहे। इसमें प्रोजेक्ट को लेकर सहमति बन गई हैं। डॉ0 एचबीएस भदौरिया, प्रबंध संचालक (म.प्र. राज्य कुक्कट विकास निगम)।

सुरक्षा गार्ड, सशस्त्र सुरक्षा गार्ड एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रशिक्षण संपन्न

भोपाल। म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग एवं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें म.प्र. द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी संघ को सहकारी संस्थाओं में मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु कार्य सौंपा गया है। जिसके तहत संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन के मार्गदर्शन में आउसोर्स कर्मचारी डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं सशस्त्र सुरक्षा गार्ड को कार्य दायित्व पर आधारभूत प्रशिक्षण संघ के श्री संजय सिंह, ओ.एस.डी, श्री जी.पी.मांझी, प्राचार्य, श्री संतोष येड़े, राज्य समन्वयक, श्री सुरेशचन्द्र वर्मा सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षक, श्रीमति मीनाक्षी बान, कम्प्यूटर प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के उपरांत प्रमाण पत्र वितरण किये गये। इस कार्यक्रम में श्री धनराज सैंदाणे, श्री विक्रम मुजुमदार, श्री विनोद कुशवाह का विशेष सहयोग रहा।

अपेक्स बैंक ने किया प्रतिभा का सम्मान

भोपाल। अपेक्स बैंक के टी.टी. नगर स्थित मुख्यालय में कार्यरत श्री छोटेलाल बाथम की पुत्री कु.साऊनी बाथम ने मध्यप्रदेश की 12 वीं स्टेट बोर्ड परीक्षा में वाणिज्य संकाय की प्राविण्य-सूची में 9 वां स्थान प्राप्त कर बैंक परिवार को गौरवान्वित किया।

कु. साऊनी की उपलब्धि पर अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री पी.एस.तिवारी द्वारा प्रतिभा का सम्मान किया गया। उक्त अवसर पर बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ओएसडी द्वय श्रीमती अरूणा दुबे श्री के.के.द्विवेदी एजीएम श्री आर.एस. चंदेल एवं श्री के.टी.सज्जन तथा प्रबंधक श्रीमती ज्योति उपाध्याय एवं श्री व्ही.के. श्रीवास्तव, उपप्रबंधक श्री समीर सक्सेना, श्री अजय देवड़ा, सहायक प्रबंधक श्री एस.के. जैन तथा पीआरओ श्री अभय प्रधान उपस्थित रहे। इस अवसर पर कृषि मंथन पत्रिका के सम्पादक श्री सुनील त्रिपाठी ने स्मृति चिन्ह प्रदान किया।

उल्लेखनीय है कि कु.साउनी के पिता का विगत 6 माह से केंसर का उपचार चल रहा है, इन्होंने परिवार की बड़ी बेटी होने पर अपने पिताजी की

गहन देखभाल करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल किया है। इनका लक्ष्य सिविल सर्विसेज या चार्टड एकाउंटेंट पर केंद्रित है।

सायबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण सम्पन्न

इंदौर। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल के सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर के द्वारा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, उज्जैन में बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों को सायबर सुरक्षा विषय पर श्री शिरीष पुरोहित, कम्प्यूटर प्रशिक्षक के द्वारा विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान करते हुए प्रशिक्षण दिया गया।

गबन, धोखाधड़ी एवं अंकेक्षण तथा विभागीय कार्य निष्पादन पर वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं सहकारी निरीक्षकों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन

भोपाल। सहकारी संस्थाओं में गबन, धोखाधड़ी एवं अंकेक्षण तथा विभागीय कार्य निष्पादन विषय पर दिनांक 27.04.2022 से 29.04.2022 तक कुल 22 प्रतिभागियों ने भारतीय दण्ड संहिता के तहत गबन, धोखाधड़ी, अमानत में खयानत की व्याख्या एवं प्रावधान विषय पर श्री डी.के. सक्सेना, आर्थिक अपराध शाखा/अधिवक्ता, वर्तमान में प्रदेश में प्राप्त महत्वपूर्ण गबन अपराधियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं अपराध पूर्व रोकथाम, विषय पर श्री अविनाश सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, भारतीय दण्ड संहिता के तहत पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं दस्तावेज व गबन, धोखाधडी, अमानत में खयानत आदि प्रकरणों का न्यायालयीन निर्णय हेतु प्रमुख तथ्य समस्या एवं समाधान विषय पर पर श्री के के सक्सेना, से.नि. डिप्टी डायरेक्टर, प्रोसिक्यूशन , संस्थाओं के वित्तीय पत्रकों का परीक्षण, तकनीकी पैरामीटर के आधार पर– सी.आर., ए.आर., एन.पी.ए. एवं अन्य पैरामीटर पर कर प्रतिवेदन दर्ज करना विषय पर श्री पी.के.एस. परिहार, वरिष्ठ प्रबंधक अपेक्स बैंक, संस्थाओं के अंकेक्षण में सी.बी.एस. एवं डी.एम. आर. एकाउंट का परीक्षण करना एवं वित्तीय अनियमित्ताओं की जानकारी प्राप्त करना विषय पर श्री आर.के. गंगेले, ओ.एस.डी., अपेक्स बैंक, संस्थाओं के वित्तीय पत्रकों के परीक्षण–निरीक्षण एवं टैक्स लायबलिटी (जी.एस.टी., आयकर आदि) का परीक्षण एवं अंकेक्षण टीप में शामिल किया जाना विषय पर परमवीर कौर, चार्टड एकाउंटेंट, सहकारी संस्था को हुई हानि की पूर्ति हेतु की जाने वाली विधिक कार्यवाही एवं पृथक वैधानिक प्रतिवेदन की जानकारी व कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यनिष्पादन, कर्तव्य, उत्तरदायित्व व द्वारा प्रशासक निर्वाचन अधिकारी, परिसमापन, अंकेक्षण श्री श्रीकुमार जोशी, सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त सहकारिता,

सहकारी संस्थाओं में गबन एवं धोखाधडी के मुख्य प्रकार एवं उनके तथ्यों का प्रकटीकरण पर श्री प्रदीप नीखरा सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त सहकारिता, वर्तमान में संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु जारी अद्यतन परिपत्र एवं उनका पालन कर वित्तीय अनियमितताओं पर रोकथाम विषय पर श्री संजीव गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, वर्क लाईफ बैलेंस, व्यक्तित्व विकास, संवैगात्मक बुद्धि, समय एवं तनाव प्रबंधन विषय पर श्रीमति सृष्टि उमेकर, कारपोरेट मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के समापन अवसर पर श्री संजय सिंह, राज्य सहकारी शिक्षा अधिकारी, श्री संतोष येड़े, राज्य समन्वयक, कार्यक्रम का संचालन श्री गणेश प्रसाद मांझी, प्राचार्य के द्वारा किया गया। श्री धनराज सैंदाणे, श्री विनोद कुशवाहा, श्री विक्रम मुजुमदार, श्री प्रवीण कुशवाह,, श्री ज्ञानू सिंह एवं समस्त स्टाफ का विशेष सहयोग रहा।

प्रदेश के पैक्स प्रबंधकों को समर्थन मूल्य की खरीदी व आर्बीटिशन प्रकरण तैयार करने संबंधी प्रशिक्षण प्रशिक्षण का आयोजन

भोपाल। पैक्स प्रबंधकों हेतु लीकेज (हानि) की रोकथाम एवं समर्थन मूल्य की खरीदी व आर्बीटेशन प्रकरण तैयार करने संबंधी प्रशिक्षण दिनांक 04 मई से 11 मई 2022 तक एक–एक दिवसीय 05 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। जिसमे 67 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण में विषय विशेषज्ञों द्वारा पैक्स प्रबंधकों को पैक्स में लिकेज(हानि) के कारण एवं नियंत्रण के उपाय, पैक्स पर कर दायित्व, जीएसटी एवं आयकर का रिटर्नस तथा पैनाल्टी, समर्थन मूल्य खरीदी में क्षति की पूर्ति हेतु आर्बीट्रेशन के तहत दावा प्रस्तुत करना एवं प्रबंधक की भूमिका, आर्बीट्रेशन की प्रक्रिया, दावा प्रस्तुति हेतु वैधानिक कार्यवाही, समर्थन मूल्य खरीदी, बिल प्रस्तुत करना, क्लेम पत्रक तैयार करना एवं आडिट कराना आदि की प्रक्रिया एवं प्रबंधक की भूमिका विषयों पर विषय विशेषज्ञों – श्री श्रीकुमार जोशी से.नि. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, श्री पी.के.एस. परिहार, से.नि. वरि. प्रबंधक, अपेक्स बैंक, श्री योगेश जैन चार्टड एकाउंटेंट, व श्री अनूप शर्मा वरि. अधिवक्ता, श्री संजय सिंह, राज्य सहकारी शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा संचालित

(म.प्र. शासन सहकारिता विभाग द्वारा अनुमोदित)

सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु
सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम

Higher Diploma in Cooperative Management (HDCM)

माध्यम - ऑनलाईन

योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण अवधि - 20 सप्ताह ऑनलाईन आवेदन/
प्रवेश की अंतिम तिथि – 31 मई 2022

कुल फीस - 20200/-

ऑनलाइन आवेदन / प्रवेश हेतु राज्य संघ के
पोर्टल www.mpscuonline.in पर विजिट करें।

संपर्क :-

म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित , भोपाल
ई- 8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल फोन : 0755-2926160 , 2926159
मो. 8770988938 , 9826876158
Website-www.mpscu.in, Web Portal-www.mpscuonline.in
Email-rajyasanghbpl@yahoo.co.in

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
किला मैदान इंदौर, म.प्र. पिन – 452006
फोन- 0731-2410908 मो. 9926451862, 9755343053
Email - ctcindore@rediffmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
हनुमान ताल जबलपुर, म.प्र पिन - 482001
फोन- 0761-2341338 मो. 9424782856 , 8827712378
Email - ctcjabalpur@gmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव
जिला छत्तरपुर, म.प्र. पिन – 471201
फोन- 07685-256344 मो. 9630661773
Email - ctcnowgong@gmail.com

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।